THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Foreign exchange reserves as on 31st January, 1991 were Rs. 4719 crores. If the IMF loan of Rs. 3250 crores is deducted from the above, the figure would be Rs. 1469 crores.

(b) The Government have initiated a number of measures to promote exports and curtail non-essential imports. Attempts are also being made to augment foreign exchange earnings through capital inflow including accelerated disbursement of external assistance.

(c) While it is difficult to quantify the results of individual measures 'in the given time frame it can be inferred that the reserves could have been much lower in the absence of these measures.

मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए फिक्की के सुझाव

*99. **श्री बलराम सिंह यादव :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1990 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में "फिक्की स्टैप्स टू चेक प्राइस राइज" के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने वर्तमान मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है, और

(ङ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) :

(क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए फिक्की ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :--

(1) बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद, का 1.5 प्रतिशत से नीचे रखा जाना चाहिए ;

(2) पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया गया 25 प्रतिशत का अधिभार, जो विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जैसे ही तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें लगभग 30 डालर प्रति बैरल गिरती जांए इसे वापस ले लिया जाना चाहिए ;

(3) मुद्रा पूर्ति के प्रसार को कम किया जाना चाहिए ;

(4) मजदूरी में की जाने वाली वृद्धि को कीमतों में वृद्धि और जीवन यापन की लागत से न जोड़कर उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए ;

(5) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए ;

(6) दालों और तिलहनों की पूर्ति में सुधार करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ; और

(7) उद्योग को मजदूरों की छंटनी करने और लागतों तथा कीमतों में कमी करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

(घ) से (ङ) मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने बहुअंगीय कार्यनीति अपनाई है। इसमें सरकारी व्यय को मॉनिटर करके सख्त राजकोषीय अनुशासन बरतना, अर्थव्यवस्था में नकदी प्रसार को रोकना, आवश्यक/संवेदी वस्तुओं की पूर्ति और मांग को और अधिक कारगर बनाना, प्रबन्ध करना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल है।